दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100
संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 04, शनिवार, 26 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

न्यूज

दो फरवरी से इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल शुरू

नई दिल्ली , (एजेंसी)। देश के अलग-अलग शहरों की विरासत, खानपान, संस्कृति और धरोहरों से आम लोगों को रूबरू कराने में अहम भूमिका निभाने वाला इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल आगामी दो फरवरी से शुरू हो रहा है। गैर सरकारी संगठन सहपीडिया के सचिव वैभव चौहान ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यूनेस्को और खनन क्षेत्र की सरकारी कंपनी एनएमडीसी के सहयोग से आगामी दो फरवरी से 28 फरवरी तक देश भर के 37 शहरों में हेरिटेज वॉक आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह हेरिटेज वॉक के आयोजन का दूसरा साल है। हेरिटेज वॉक की शुरूआत गुजरात के अहमदाबाद शहर से होगी। वॉक का मुख्य केंद्र इस शहर का धार्मिक इतिहास और विभिन्न धर्मों के लोगों का सह अस्तित्व होगा। पहले साल करीब 2,500 प्रतिभागी हेरिटेज वॉक में शामिल हुए थे और टियर दो और टियर तीन के शहरों में लोगों ने इसमें बढ़चढ कर हिस्सा लिया।

जेनेवा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के नजदीक विस्फोट

जेनेवा , (एजेंसी)। स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा संबंधी एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जेनेवा में उसके वाणिज्य दूतावास के नजदीक विस्फोट की होने की रिपोर्ट है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक विस्फोट बिजली की तार में खराबी के कारण हुआ है। जेनेवा पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के नजदीक हुआ यह विस्फोट जमीन के भीतर बिजली की तार में गड़बड़ी के कारण हुआ। विस्फोट के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जेनेवा के पुराने इलाके में स्थित है जहां यह विस्फोट हुआ।

हिमस्खलन के बाद लापता दो शिकारियों की तलाश शुरू

श्रीनगर , (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन के बाद लापता दो शिकारियों की तलाश के लिए गुरुवार को व्यापक पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तीन स्थानीय लोग बुधवार को तड़के कुपवाड़ा जिले में लोलाब के रंग वारनो जंगल में शिकार करने गये थे। इनमें से एक व्यक्ति शाम में लौटकर आया और पुलिस को सूचित किया कि जब वे जंगल में घूम रहे थे तभी हिमस्खलन हुआ। उसने पुलिस और ग्रामीणों को बताया कि इसके बाद उसके साथ गये बशीर अहमद हजाम और इमामदीन हजाम लापता हैं।

वेनेजुएला में प्रदर्शन के दौरान 152 लोग हिरासत में

काराकास , (एजेंसी)। वेनेजुएला में सोमवार से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान अब तक कम से कम 152 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वेनेजुएला फोरो पेनल मानवाधिकार संगठन के प्रमुख अल्फ्रेडो रोमेरो ने ट्विटर पर लिखा है कि सोमवार को नौ लोगों तथा मंगलवार को 34 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं बुधवार को 109 लोगों को हिरासत में लिया गया। उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता जुआन गुएडो ने बुधवार को खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उधर अमेरिका ने श्री गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से इस्तीफा देने और श्री गुएडो को राष्ट्रपति बनाने की अपील की है।

किम जोंग ने शुरू की दूसरी शिखर बैठक की तैयारी

प्योंगयांग , (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे शिखर बैठक की तैयारियां शुरू करने के आदेश दिये हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि श्री किम जोंग ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछले सप्ताह मुकालात करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। वे अमेरिका के साथ बैठक के नतीजों से वह खुश हैं। उन्होंने अधिकारियों को अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे शिखर सम्मेलन (बैठक) की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये। उ. कोरिया के उप नेता किम योंग चोल ने 18 जनवरी को व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप से मुलाकात की थी।

अभिनेत्री और बीजेपी नेत्री मौसमी चटर्जी ने एंकर को दी सही कपड़ों की नसीहत

मंदिर में जींस पहनकर नहीं जा सकतीं

सूरत ,(एजेंसी)। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने एक एंकर पर तंज कसते हुए उन्हें सही कपड़े पहनने की नसीहत डे डाली। दरअसल मौसमी चटर्जी गुजरात के सूरत में एक इवेंट में शामिल हुई थीं। यहां उन्होंने एक एंकर के कपड़ों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। बता दें कि एंकर ने इवेंट में कैजुअल पैंट सूट पहना था। मौसमी चटर्जी ने इवेंट में एंकर से कहा क आप जगह के हिसाब से ये समझिए कि क्या पहनना चाहिए। मंदिर में आप जींस पहनकर जा नहीं सकती हैं, इससे आपको तकलीफ होगी, तो इससे अच्छा सलवार कमीज पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, लहंगा चोली पहन लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। मौसमी ने आगे यह भी कहा कि अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक मां की तरह आपको कह रही हूं।

कैसे आया पृथ्वी में जीवन, अध्ययन से हुआ खुलासा

वॉशिंगटन ■ एजेंसी

भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य ऐसे तत्वों की प्राप्ति ग्रहों की टक्कर की उस घटना के बाद हुई जिसके परिणामस्वरूप 4.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी।

अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के राजदीप दासगुप्ता ने कहा, ''प्राचीन काल में उल्कापिंडों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों को लंबे समय से ज्ञात था कि पृथ्वी और सौर मंडल की आंतरिक कक्षाओं में स्थित चट्टानों वाले अन्य ग्रहों में विघटन होकर तत्व निकलते रहते हैं, लेकिन इसके समय और प्रणाली पर बहस चलती रही। 'साइंस एडवांसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के सह-लेखक दासगुप्ता के अनुसार, ''हमारी खोज पहली है जो सभी भू-रासायनिक साक्ष्यों के अनुरूप समय की व्याख्या कर सकती है।

राइस यूनिवर्सिटी के स्नातक के छात्र दमनवीर ग्रेवाल ने प्रयोगों की कड़ी में लंबे समय से माने जा रहे इस सिद्धांत के परीक्षण के लिए साक्ष्य जुटाये कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार तत्व एक ग्रह के साथ टक्कर के बाद पैदा हुए जिसके केंद्र में सल्फर की बहुतायत थी. ग्रेवाल के अनुसार पृथ्वी पर कार्बन-नाइट्रोजन का अनुपात और कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर की पूरी मात्रा चंद्रमा की उत्पत्ति के संगत है

'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन पर ट्रंप और पेलोसी में तनातनी

पेलोसी पहले भी कर चुकी हैं संबोधन स्थगित करने का अनुरोध

वॉशिंगटन ■ एजेंसी

'स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैंसी पेलोसी के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। दरअसल ट्रम्प ने पेलोसी को पत्र लिखकर कहा कि वह निर्धारित समय पर ही 'स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन देना चाहता है, जिसके बाद पेलोसी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पेलोसी पहले भी ट्रम्प को पत्र लिखकर संबोधन स्थगित करने का अनुरोध कर चुकी हैं।

राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा की स्पीकर के निमंत्रण पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में पारंपरिक 'स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन देता है। इस समय स्पीकर के पद पर पेलोसी नियुक्त हैं। पेलोसी ने ट्रम्प को लिखे एक पत्र में कहा कि मैं आपको पत्र लिखकर यह सूचित कर रही हूं कि प्रतिनिधि सभा सरकार के कामकाज पुनः आरंभ करने तक राष्ट्रपति के 'स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी।

इससे पहले ट्रम्प ने पेलोसी को पत्र लिखकर कहा था कि मैं प्रतिनिधि सभा के चेम्बर में 29 जनवरी की शाम को आपसे मिलने का इच्छुक हूं। यदि स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन निर्धारित समय पर और विशेषकर, तय स्थान पर नहीं होता है तो यह देश के लिए दुःखद होगा। इसके तत्काल बाद पेलोसी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का 29 जनवरी को कांग्रेस में स्वागत नहीं है. पेलोसी से पत्र मिलने के बाद ट्रम्प ने कहा कि वह जल्द ही इस बात की घोषणा करेंगे कि आगे क्या करना है।

समय पर पेलोसी को देंगे जवाब

हम आने वाले समय में नैंसी पेलोसी को जवाब देंगे, लेकिन वह अमेरिकी लोगों के साथ, हमारे संविधान के साथ जो कर रही हैं, वह अशोभनीय है। ट्रम्प ने मेक्सिको के साथ लगती देश की सीमा पर दीवार बनाने को लेकर अपने रुख में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि पेलोसी ने जो किया वह बहुत बुरा है। इसके बाद उन्होंने एक अन्य बैठक में आरोप लगाया कि पेलोसी ने स्टेट ऑफ द यूनियन इसलिए रद्द किया क्योंकि वह नहीं चाहतीं कि अमेरिकी लोगों को सच पता चले।

दो हादसों से दहला गुरुग्राम, चार मंजिला इमारत ढही और 200 झुग्गियां जलीं

मलबे से निकले छह शव

गुरुग्राम ■ एजेंसी

उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा हो गया है। कोहरे की वजह से हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तीन लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।

घटना हाथरस जिले में हुई है। भरतपुर-बरेली रेलवे लाइन पर कोटा-पटना ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें तीन एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। यह हादसा घने कोहरे के चलते हुआ।

हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर से यह एक ही परिवार के 3 लोग एटा में अपने भाई से मिलने के लिए हाथरस रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। मृतकों में शेष कुमार पुत्र सुरेश चंद्र, ऋषभ पुत्र शेष कुमार, सवू पुत्री संजय शामिल है। एभी एक व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास जारी है। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुच गयी है।

कैमरून में सड़क दुर्घटना 20 लोगों की मौत

याओंडे , (एजेंसी)। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून में गोओंडेरे-टोबरो हाईवे पर दोपहर हुई एक सड़क दुर्घटना में बच्चों समेत करीब 20 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक ट्रक एक बस से टकरा गया। इस दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज गोओंडेरे के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। कैमरून के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1200 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है।

तेलंगाना कांग्रेस का विवादित पोस्टर

बीजेपी ने कहा- महिलाओं का अपमान, माफी मांगें राहुल गांधी

हैदराबाद ■ एजेंसी

तेलंगाना कांग्रेस के एक पोस्टर पर इन दिनों जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दौपद्री वस्त्रहरण का पोस्टर बनाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए हिंदू महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की है।

पोस्टर में तेलंगाना में लोकतंत्र को द्रौपदी और धृतराष्ट्र को चुनाव आयोग के रूप में पेश करते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एजेंट द्वारा लोकतंत्र के शोषण का आरोप लगाया है। इसमें दुशासन को चुनाव आयोग का एजेंट बताया है। तेलंगाना कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन को-ऑर्डिनेशन कमिटी ने चुनाव आयोग पर टीआरस के प्रति झुकाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग के खिलाफ तेलंगाना में इंदिरा पार्क के पास धरना चौक पर प्रदर्शन करेगी।

राहुल या प्रियंका पर कोई कार्टून बना दे तो कैसा लगेगा?

इससे पहले कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एम. शशिदरे ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने कई बार शिकायत की गई और वोटर लिस्ट की विसंगतियों का मुद्दा उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई श्री श्री 50 साल के राहुल गांधी या फिर नई महासचिव प्रियंका गांधी पर कार्टून बना दे तो कैसा लगेगा? कांग्रेस की तेलंगाना में बुरी तरह फजीहत हुई है और अब वह इस तरह के कार्टून का सहारा ले रही है, यह शालीनता की सीमा से परे है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 16 लोगों की मौत

मैड्रिड , (एजेंसी)। वेनेजुएला में मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के पोर्टुगुएसा, बारिनास, तचिरा, कारावस, अमेजनास और बोलिवर राज्यों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो ने स्वयं को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने श्री जुआन गुआइदो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है।

दम घुटने से एक बच्चे की मौत, सात गंभीर

बाढ़ , (एजेंसी)। बिहार में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गोसाईमठ मुहल्ला में आग से निकले धुंआ से दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गयी तथा सात अन्य बेहोश हो गये। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि गोसाईमठ मुहल्ला निवासी रामनाथ सिंह के घर देर रात एक कमरे में आठ लोग सोये हुए थे तभी बोरसी की आग से निकले धुंआ से एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई जबकि सात अन्य बेहोश हो गए। मृतक की पहचान आशीष कुमार के रूप में की गयी है।

बादल ने पंजाब में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया

चंडीगढ़ , (एंजेसी)। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दावोस में चल रहे सम्मेलन में भाग ले रहे पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ बातचीत की।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य और उद्योग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन और इन्वैस्ट पंजाब के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल शामिल हैं। श्री बादल ने विभिन्न सत्रों में कई वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने व्यापारिक और औद्योगिक गतिशीलता के विषयों पर दो सत्रों में हिस्सा लिया। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण को बचाने के लिए उद्योग को सहयोग देने का आहवान किया।

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में निवेश के अवसरों ख़ास तौर पर आई.टी., ऑटोमोबाईल -ई व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में अपार संभावनाओं के बारे अवगत करवाया। प्रमुख व्यापारिक नेताओं में नैस्ले के कार्यकारी उप प्रमुख और सी.ई.ओ. एशिया, ओशनिया और सब सहारन अफ्रीका क्रिस जौहनसन, नैसपर्ज़ के उप प्रमुख, कॉर्पोरेट मामले और सार्वजनिक नीति ड्रिक डैलमारटिनो, जे.बी.एम. ग्रुप के कार्यकारी निदेशक निशांत आर्य और अवादा के भाविन शाह (नीति) और नितिन मित्तल (उप प्रमुख कॉर्पोरेट वित्त) शामिल हैं।

एससी-एसटी संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में संशोधनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही लंबित पुनर्विचार याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

पिछले साल पिछले साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में सेक्शन 18 जोड़ दिया था जिसने इस तबके के लहिलाफ अपराधों को गैर जमानती बना दिया था। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में रिटायर हो चुके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने पिछले साल मार्च में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में तुरंत गितफ़्तार पर रोक लगाकर जांच की बात कही थी। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी।

गैर सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य थी।

जिसके बाद एससी एसटी समुदाय की नाराजगी और राजनीतिक दबाव में आकर केंद्र ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी मगर कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस मामले के अग्रिम जमानत के प्रावधान करने के अपने आदेश को सही मानते हुए कहा कि यह जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में अधिकतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि न्यूनतम सजा छह महीने है। जब न्यूनतम सजा छह महीने है, तो अग्रिम जमानत का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए।

NARAYAN YADAV
M. 99046 85319
M. 96626 26763
DHARA DEVELOPERS
Sale, Purchase & Rent for Flat, Shop, Plot, Industrial Sheds
705, City Center, Nr. Sosyo Circle, U. M. Road, Surat.

स्व. धनपत्तीदेवी जगदेवप्रसाद मौर्य शिक्षा एवं जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित
महावीर हिन्दी विद्यालय
विशेषताएं :
❖ हर कक्षा में CCTV केमरा
❖ कम्प्यूटर क्लास
❖ समय-समय पर प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है ।
❖ B.Ed शिक्षक के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था
26 JANUARY
ट्रस्टी प्रमुख : श्री लहुरीराम मौर्य
(कक्षा 1 से 8 तक)
401-409, मणिनगर, बमरोली रोड, बमरोली, सूरत ।
मो. 96623 84290

वीरता राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्ची को पौधा देकर किया सम्मानित

पीएम मोदी ने नन्ही ईहा के साथ खूब की मस्ती

मेरठ ■ एजेंसी

बेटी पर गर्व

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाली ईहा दीक्षित गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। इस दौरान ईहा ने पीएम मोदी के साथ पौधरोपण किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भी ईहा को पौधा देकर सम्मानित किया। इस बीच करीब 7 से 10 मिनट तक पीएम मोदी ईहा से मिले। उन्होंने ईहा की सराहना करते हुए कहा कि तुम अच्छा काम कर रही हो, इसे भविष्य में जारी रखना।

ईहा ने पीएम मोदी से काफी बातें कीं और उनके साथ मस्ती भी की। वहीं पीएम मोदी ने ईहा के सिर पर हाथ रखकर उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाली ईहा दीक्षित को स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने भी बधाई दी। लोहिया नगर स्थित सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल में कक्षा-एक में पढ़ने वाली ईहा का कक्षा में भी उत्तम प्रदर्शन रहता है।

प्रधानाचार्य सौमेन चक्रवर्ती ने कहा कि वह अपने सहपाठियों के साथ मधुर व्यवहार करती है। अन्य बच्चों को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित करती है। प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि यहां से पढ़ रही बच्ची ने देश में नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि ईहा को स्कूल की तरफ से भी जल्द सम्मानित किया जाएगा। बालशक्ति पुरस्कार पाने वाली मेरठ की बेटी ईहा दीक्षित के पिता कुलदीप शर्मा ने बताया था कि ईहा को प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए अलग से सात मिनट का वक्त मिला है। इस मुलाकात में ईहा प्रधानमंत्री के साथ उनके बगीचे में पौधा रोपेंगी।

बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के सेशन का पूरा अभ्यास उसको कराया गया। इस दौरान उसने कहा, 'नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम ईहा दीक्षित है, मैं मेरठ यूपी से हूं'। इसके बाद वह पीएम को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगी और पौधरोपण के लिए पौधा देंगी। ईहा के साथ महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी होंगी।

रिवरफ्रंट घोटाला ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी

लखनऊ ,(एजेंसी)। रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यूपी समेत चार राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लखनऊ के विशालखंड में भी ईडी ने छापेमारी की।

ईडी ने इंजीनियरों व ठेकेदारों का घर खंगाला। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि गोमती रिवरफ्रंट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद इसमें घोटाले की बात कहकर सीबीआई से जांच कराने की गुजारिश की थी।जिसके बाद सीबीआई ने जांच की थी और इंजीनियरों के बयान दर्ज किए थे।

संपादकीय

लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव नियुक्त किया व उत्तर प्रदेश-पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी। वैसे, प्रियंका के लिए राजनीति उतनी आसान नहीं होगी। इंदिरा गांधी की छवि के साथ कितना न्याय कर पाएंगी यह एक बड़ी बात होगी। वहीं जहां मोदी एक बड़े ब्रांड के तौर पर पहले से ही मौजूद हैं वहां प्रियंका कितना असर छोड़ पाएंगी यह कह पाना मुश्किल है।

राहुल गांधी का एक और मास्टर स्ट्रोक

लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव नियुक्त किया व उत्तर प्रदेश-पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी। इस नियुक्ति के साथ ही प्रियंका का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो गया। उनकी नई भूमिका पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और राजनीति में सकारात्मक बदलाव आएगा। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव-प्रभारी (उत्तर प्रदेश-पश्चिम) बनाया गया है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में कार्यभार संभालेंगी। प्रियंका की राजनीतिक गतिविधि एक लंबे समय से अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और भाई राहुल गांधी के निवार्चन क्षेत्र अमेठी तक ही सीमित थी।

प्रियंका की नियुक्ति के बाद राहुल गांधी ने अमेठी में संवाददाताओं से कहा, 'मैंने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिशन दिया है कि वे राज्य में कांग्रेस की सच्ची विचारधारा...गरीबों व कमजोर लोगों की विचारधारा...सबको आगे लेकर बढ़ने की विचारधारा को आगे बढ़ाएं।' उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में नए तरीके की सोच आएगी और राजनीति में सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान देने के फैसले से यूपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं और वे सभी कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम को 'गेम चेंजर' मान रहे हैं। चुनावी साल में प्रियंका की महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ता आशावादी हैं। प्रियंका पार्टी नेताओं के करीब रही हैं और संगठनात्मक स्तरों पर कई बदलाव आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और मोतीलाल वोरा ने कहा कि प्रियंका की नियुक्ति से देशभर में कांग्रेस पार्टी की फिर वापसी होगी।

प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति का फैसले ऐसे वक्त पर लिया गया है जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। पिछले महीने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन करने और उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किए जाने के बाद राज्य में कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तरजीह नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस ने शुरुआत में इस बात की घोषणा की है कि वे राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि, बाद में कांग्रेस ने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के गठबंधन के उनके रास्ते खुले हुए हैं। बहरहाल, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दस सीटें आती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री को कांग्रेस के ट्रंप कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव बनाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पूर्वांचल प्रभारी बनाकर आलाकमान ने यह संकेत दिए हैं कि यूपी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है।

प्रियंका गांधी के खुलकर राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं का तो जोश बढ़ेगा ही, इसके अलावा कांग्रेस के इस दांव से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रियंका के सहारे कांग्रेस, सपा-बसपा गठबंधन के अलावा भाजपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती है। खासकर युवा वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। प्रियंका को यूपी का प्रभारी बनाए जाने के साथ संभावनाएं इस बात की भी बनने लगी हैं कि वह रायबरेली या इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट में से किसी पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ीं तो प्रियंका के रायबेरली से चुनाव लड़ने की संभावना अधिक है। फिलहाल कांग्रेस ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। सभी 80 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़े जाने की बात भी कही जा रही है। अब विपक्ष का रवैया देखना है कि वह प्रियंका की इमेज को कैसे जनता के बीच में पेश करता है।

बहरहाल, कांग्रेस ने प्रियंका के चेहरे को यूपी में आगे जरूर कर दिया है, लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके सामने मोदी और माया जैसे धुरंधर होंगे, जो विरोधियों की हर चाल की काट जानते हैं, जिन्हें बाल की खाल निकालने में महारत हासिल है। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो उस समय प्रियंका लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ी थीं, लेकिन मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में जरूर उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका की सियासत पर मजबूत पकड़ होने की छाप स्पष्ट दिखाई दी तो कुछ लोगों को प्रियंका में इंदिरा की छवि नजर आई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान तब के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर प्रियंका के एक विवादित बयान की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। प्रियंका ने चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में कह दिया था कि मोदी नीची राजनीति करते हैं।

मोदी ने प्रियंका के इस बयान को अपनी जाति से जोड़कर कहना शुरू कर दिया कि मेरी जाति को नीच बताया जा रहा है। मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया जिसका फायदा भी भाजपा को मिला था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका के आने से महिला वोटरों का रुझान उनकी तरफ बढ़ेगा साथ ही सवर्ण वोटरों को एक बड़ा तबका भी प्रियंका के नाम पर कांग्रेस के साथ जा सकता है। वैसे, कांग्रेस के इस फैसले के साथ ही पार्टी के लिए कई मुश्किलें और बढ़ेंगी। पहला यह कि विरोधी पार्टियां पहले ही कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई हैं जो इस फैसले के साथ और तेजी से विरोध की वजह बनेगा। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामलों को लेकर विरोधी पार्टियां तेजी से घेराव करेंगी जिसका सामना दोनों को ही करना होगा। कई जगह यह भी माना जा रहा है कि प्रियंका अगर समय के साथ पार्टी में खुद को साबित करती चलीं गईं तो राहुल के साथ-साथ दो नेतृत्व तैयार हो जाएंगे। जो पार्टी के लिए निगेटिव असर ला सकते हैं लेकिन यह भविष्य में तय होगा।

कहा जाता है कि प्रियंका के पहनावे, बोलचाल और भाषण कला में उनके चाहने वालों को इंदिरा की छवि दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करते हुए उनकी भाषण कला को बहुत बेहतर बताया जाता रहा है। वहीं यह भी कहा जाता है कि प्रियंका अपने पिता की तरह जनता से सीधे संवाद करने के लिए जानी जाती हैं। शुरू से ही प्रियंका को राजनीति में लाने के लिए यही तर्क दिए जाते थे। साथ ही इंदिरा की छवि की वजह से उनकी आम जनता और चाहने वालों में लोकप्रियता पहले भी काफी रही है। प्रियंका की राजनीति में एंट्री कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए बड़े सपोर्ट के तौर पर देखी जाएगी। बताया जाता है कि पार्टी के कई फैसलों में प्रियंका की अप्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदारी रहती है लेकिन अब वह सीधे तौर पर पार्टी में महासचिव के पद पर प्रभाव छोड़ेंगी, जो कि कांग्रेस के लिए मास्टरस्ट्रोक बताया जा रहा है। इन कारणों को देखते हुए कह सकते हैं कि प्रियंका के लिए राजनीति उतनी आसान नहीं होगी। इंदिरा की छवि के साथ कितना न्याय कर पाएंगी यह एक बड़ी बात होगी। वहीं जहां मोदी एक बड़े ब्रांड के तौर पर पहले से ही मौजूद हैं वहां प्रियंका कितना असर छोड़ पाएंगी यह कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस के जो हालात हैं उससे राहुल के साथ प्रियंका पर भी बड़ी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। खासतौर पर यूपी में खुद को साबित करना बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि यूपी केंद्र की राजनीति तय होती है।

प्रो. रामशंकर मिश्र
(राजनीतिक विश्लेषक)

विचार

सरकार के काम पर लगी मुहर

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 व 2020 में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की नीतियों पर मुहर है। अब मोदी सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करती रहे।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 और 2020 में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और इसकी गति चीन ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग, अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख और पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है। चीन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहां 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और 2019 में और अधिक गिरावट के साथ 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके लिए ट्रेड वॉर को भी जिम्मेदार बताया गया है।

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5 प्रतिशत व 2020 में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इन दो साल के दौरान चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक फीसदी अधिक रहेगी। 2019 और 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अब संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थव्यवस्था को लेकर दी गई रिपोर्ट साबित करती है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं। अर्थव्यवस्था की बढ़त और उसके स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि कारोबारी गतिविधियां सुगमता से जारी रहें। इस प्रक्रिया में समय-समय पर नियमों और नीतियों में अपेक्षित सुधार भी जरूरी होते हैं। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेक ऐसे बड़े निर्णयों को अंगीकार किया है, जिनसे अर्थव्यवस्था को तात्कालिक झटका तो लगा, पर अब उनके लाभ दिखने लगे हैं। नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली यानी जीएसटी, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का निवारण, बैंकिंग सुधार, दिवालिया कानून आदि पहलों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

फिर व्यापारिक सुगमता के लिहाज से वैश्विक समुदाय में भारत की लंबी छलांग इस बात का ठोस प्रमाण है कि आर्थिक सुधारों के कारण कारोबार लगाने व बढ़ाने का समुचित माहौल बन रहा है। नई नीतियां बनाने और पुरानी नीतियों में संशोधन की धीमी प्रक्रिया भी आर्थिक विकास के लिए बाधक बनी हुई थीं। 2014 के बाद आई सुधारों की तेजी ने कारोबारियों को आकर्षित किया है। इसी का नतीजा है कि विकास दर में बढ़त है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की हलचलों को हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक बर्दाश्त कर सकने की हालत में है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अपना काम करती रहे।

भाषा की मर्यादा भूलते नेता

उत्तर प्रदेश में मुगलसराय क्षेत्र से भाजपा की विधायक साधना सिंह की बसपा प्रमुख मायावती पर की गई टिप्पणी ने फिर यह सवाल उठा दिया है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे नेता भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां अपने दुश्मन की गरिमा का भी खयाल रखने की परंपरा रही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने के बावजूद किसी नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसे मजबूत करेगा?

एक स्वस्थ और सभ्य लोकतांत्रिक प्रणाली में विचारों का मतभेद व उनके बीच टकराव एक स्वाभाविक स्थिति है, पर इसमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के विचारों के विरोध का स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक-दूसरे के सम्मान का हनन न हो। अगर इस मामूली बात का खयाल रखा जाता है तो इससे न केवल किसी व्यक्ति या फिर नेता के अपमान से बचा जा सकता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व की गरिमा भी बरकरार रखी जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अलग-अलग दलों के नेताओं की ओर से जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उनके बीच न सिर्फ अपने विपक्ष में मौजूद शख्सियतों, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं तक के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। ताजा विवाद उत्तर प्रदेश में मुगलसराय क्षेत्र से भाजपा की विधायक साधना सिंह के उस बयान से उठ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं।

एक जनसभा में भाषण देते हुए उन्होंने मायावती के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, कोई भी सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता, वह भले ही खुद उनकी पार्टी का हो या उनका समर्थक हो। शायद यही वजह है कि उनके बेलगाम बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आखिरकार उन्हें अपनी कही बातों पर खेद जाहिर करना पड़ा। सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में एक महिला नेता के अहम योगदान की अनदेखी करते हुए सिर्फ क्या उनका अपमान इसलिए किया जाना चाहिए कि भाजपा की नेता उन्हें अपना विपक्ष मानती हैं? भारत जैसे देश में जहां अपने दुश्मन की गरिमा का भी खयाल रखने की परंपरा रही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने के बावजूद किसी एक नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का ऐसा प्रयोग आखिर किसे मजबूत करेगा? विडंबना यह है कि साधना सिंह ने यह टिप्पणी जिस मंच से की, वहां भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन वहां किसी को जरूरी नहीं लगा कि इस भाषा पर खेद जताएं या विधायक को ऐसा करने के लिए कहें।

ऐसी स्थितियों का हासिल आमतौर पर सकारात्मक नहीं होता है। मामले के तूल पकड़ने के बाद न सिर्फ साधना सिंह को अपनी बातों के लिए माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उनकी पार्टी को भी बयान के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि, यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें कोई नेता अपने विपक्षी की आलोचना करते हुए इस कदर बहक गया कि उसे खुद अपनी गरिमा का खयाल भी नहीं रहा। इससे पहले भी कई अवसरों पर कुछ नेता बदजुबानी का प्रदर्शन कर चुके हैं। सवाल है कि इस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? अपने समर्थकों को खुश करने या अपनी भड़ास निकालने के लिए मतभेद या फिर आलोचना को सामंती जुबान में अभिव्यक्त किए जाने का चलन कैसा राजनीतिक परिदृश्य रचेगा? आखिर इस तरह की बदजुबानी किसके हक में है? इस तरह के बेलगाम बयानों से किसी नेता को फौरी फायदा मिलता हुआ भले दिखे, लेकिन सच तो यह है कि दूरगामी असर के रूप में खुद उसके व्यक्तित्व की गरिमा कम होती है। बल्कि आज इस तरह की बोली वाले नेताओं की समझ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेना बंद कर रहे हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर इस तरह की प्रवृत्तियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में हमारे लोकतंत्र के सामने कुछ जटिल चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

हद तो तब हो गई,जब बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक विजय यादव ने साधना सिंह को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने साधना सिंह का सिर उनके पास लाने वाले को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। यानी जो गलती साधना सिंह ने की, वही विजय यादव भी दोहराने लगे। भारतीय राजनीति में भाषा की ऐसी गिरावट शायद पहले कभी नहीं देखी गई। ऊपर से नीचे तक सड़कछाप भाषा ने अपनी बड़ी जगह बना ली है। लोग निरंतर अपने बड़बोलेपन से ही मैदान जीतने की जुगत में हैं और उन्हें लगता है कि यह 'टीवी समय' उन्हें चुनावी राजनीति में स्थापित कर देगी। दिखने और बोलने की संयुक्त जुगलबंदी ने चैनलों को कच्चा माल उपलब्ध कराया हुआ है तो राजनीति में जल्दी स्थापित होने की त्वरा में लगे नए युवा भी भाषा की विद्रूपता का ही अभ्यास कर रहे हैं।

यह गिरावट चौतरफा है। बड़े रास्ता दिखा रहे हैं, नए उनसे सीख रहे हैं। टीवी और सोशल मीडिया इस विद्रूप का प्रचारक और विस्तारक बना हुआ है। न पद का लिहाज, न आयु का और न ही भाषा की मर्यादा-सब इसी हमाम में नंगे होने को आतुर हैं। राजनीति से व्यंग्य गायब है, हंसी गायब है, परिहास गायब है- उनकी जगह गालियों और कटु वचनों ने ले ली है। राजनीतिक विरोधी के साथ शत्रु की भाषा बोली और बरती जा रही है। यह संकटकाल बड़ा है और कठिन है। पहले एकाध आजम खां, मायावती और आदित्यनाथ थे। आज सब इन्हें हटाकर खुद को उनकी जगह स्थापित करना चाहते हैं। केंद्रीय राजनीति के सूरमा हों या स्थानीय मठाधीश कोई भाषा की शुचिता का पालन करता नहीं दिखता। जुमलों और कटु वचनों ने जैसी जगह मंचों पर बनाई, उसे देखकर हैरत होती है। बड़े पदों पर आसीन राजनेता भी चुनावी मोड में पद की मर्यादा भूलकर जैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन समय करेगा। किंतु इतना तो यह है कि यह समय राजनीति भाषा की गिरावट का समय बन चुका है।

आलोचना, विरोध, षड्यंत्र का अंतर भी लोग भूल गए हैं। आलोचना अगर स्वस्थ तरीके से की जाए, अच्छी भाषा में की जाए तो भी प्रभाव छोड़ती है। अच्छी भाषा में भी कड़ी से कड़ी आलोचना की जा सकती है। किंतु इस टीवी समय में राजनेता की मजबूरी कुछ सेकंड की बाइट में बड़ा प्रभाव छोड़ने की रहती है। ऐसे में वह कब अपनी राह से भटक जाता है उसे खुद भी पता नहीं लगता। भाषा की गिरावट का यह दौर आने वाले समय में भी रुकने वाला नहीं है। टीवी से सोशल मीडिया, फिर मोबाइल टीवी तक गिरावट जारी ही रहने वाली है। समय का संकट यह है कि राजनीति में आदर्श हाशिए पर हैं। शुचिता और पवित्रता के सवाल राजनीति में बेमानी लगने लगे हैं। जिनकी वाणी पर देश मुग्ध रहा करता था ऐसे राजनेता न सिर्फ खामोश हैं बल्कि काल के प्रवाह में वे अप्रासंगिक भी लगने लगे हैं। संसद से लेकर विधानसभाओं तक में बहस का स्तर गिर रहा है। नेता सदनों से भाग रहे हैं और मीडिया पर सारी जंग लड़ने पर आमादा हैं। ऐसे कठिन समय में नेताओं, दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को नई राह तलाशनी होगी। उन्हें नया पथ बताना होगा जिसमें स्वस्थ संवाद की बहाली हो।

आज जबकि राजनीति के मैदान कीचड़ से सने हैं, तो भी हमें इसकी सफाई के लिए कुछ जतन तो करने ही होंगे। चुनाव अवसर होते हैं जब राजनीतिक दलों और राजनीति के शुद्धिकरण की सोच रखने वालों को इसकी शुचिता पर सोचना ही चाहिए। यह पहल हमने आज नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। हर बार नेताओं की बदजुबानी के बाद समाज में आवाज उठती है, मगर वह नेताओं के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है।

शादाब खान
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

मोदी सरकार ने आने के बाद से ही अर्थव्यवस्था में सुधार के जो प्रयास शुरू किए हैं, वह आगे भी जारी रहेंगे। सरकार की नीतियों को वैश्विक समर्थन मिल रहा है।

एसपी शुक्ल, वित्त राज्यमंत्री

अर्थव्यवस्था में बेहतरी के जो दावे सरकार कर रही है, उसमें खोट नजर आता है। देश में हर स्तर पर नाकामी है, ऐसे में यह कैसे मान लें कि अर्थव्यवस्था बेहतर है।

मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता

सत्यार्थ

प्रियजनों का कष्ट असहनीय

आंध्रप्रदेश में बम्मेर पोतन्ना एक संत थे। एक दिन वे अष्टम स्कंध का गजेंद्र मोक्ष प्रसंग लिख रहे थे, तभी उनका साला श्रीनाथ आया और पढ़ने लगा-मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ा और वह उसे निगलने लगा। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए व उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। पुकार सुन भगवान तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जल्दी में सुदर्शन चक्र लेने का ध्यान न रहा। वह इतना पढ़ कर रुक गया और अपने बहनोई का मजाक उड़ाते हुए बोल पड़ा-आपने कैसे लिखा कि भगवान को सुदर्शन चक्र लेने का ध्यान न रहा। वे क्या लड़ाई देखने जा रहे थे? यदि सुदर्शन चक्र साथ में न ले जाते, तो गजेंद्र की मुक्ति कैसे होती? कोई काव्य लिखने से पहले उसे अनुभव की कसौटी पर परखना जरूरी होता है। पोतन्ना उस वक्त तो चुप रहे, पर दूसरे दिन उन्होंने श्रीनाथ के लड़के को दूर खेलने भेज दिया और पास के एक कुएं में एक बड़ा पत्थर डाल कर चिल्लाने लगे- श्रीनाथ! दौड़ो, तुम्हारा बच्चा कुएं में गिर गया है। श्रीनाथ ने सुना, तो वह बिना कुछ सोचे कुएं में कूदने लगा। यह देख पोतन्ना ने उसे पकड़ लिया और बोले- मूर्ख हो क्या, जो बिना कुछ सोचे कुएं में कूद रहे हो? बच्चे को निकालोगे कैसे? रस्सी-बाल्टी तो साथ में लाए नहीं। श्रीनाथ जब सोचने लगा, तो पोतन्ना बोले- घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा गिरा नहीं है। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि जिसके प्रति प्रेम ज्यादा हो, उस पर संकट आने पर मनुष्य की क्या दशा होती है। जिस प्रकार पुत्र-प्रेम में तुम्हें रस्सी-बाल्टी लेने का ध्यान न रहा, उसी प्रकार भगवान भी सुदर्शन चक्र लेना भूल गए। तब श्रीनाथ ने जाना कि प्रियजनों के कष्ट की बात सुन मनुष्य तो क्या, भगवान भी सुध-बुध खो बैठते हैं।

राधा नाचीज

सार-समाचार

भारत विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है: सिंगापुर मंत्री

सिंगापुर। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत तेजी से विकास कर रहा है और तकनीकी एवं सामाजिक नवोन्मेष में अग्रणी बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री गान किम योंग ने भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार रात को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत एवं सिंगापुर के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल है ।इसके बाद से दोनों देशों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच इस साल राजनयिक संबंधों का 54वां साल है। योंग ने कहा, ''भारत आज विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर उभरा है। देश अपनी समृद्ध हिरासत को संरक्षित रखते हुए तकनीक एवं सामाजिक नवोन्मेष को आगे रख कर तेजी से विकास कर रहा है।''उन्होंने कहा, ''सिंगापुर ने हमेशा भारत का विकास चाहा है और हमें भारत को तेजी से आगे बढ़ते और क्षेत्र एवं दुनिया में बड़े स्तर पर योगदान देते देखने में खुशी हो रही है।''मंत्री ने साझा हितों और मूल्यों पर स्थापित दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं में पिछले साल हुई उच्च स्तरीय वार्ता का जिक्र किया ।योंग ने रूपे और सिंगापुर के नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर्स का जिक्र करते हुए कहा, ''हमने फिनटेक (वित्तीय तकनीक) नवोन्मेष की हमारी रणनीतिक साझीदारी के नए स्तम्भ के तौर पर पहचाना है।''उन्होंने डिजिटल तकनीक में सहयोग को स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार देने की बात रेखांकित की। उन्होंने आधार लागू करने में भारत की सफलता का जिक्र किया।

क्या कॉरपोरेट टैक्स में कारोबारियों को मिलेगी राहत?

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्री ने अपने पिछले आम बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में भले ही कोई बदलाव न किया हो, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी थी। काफी दिनों से कारोबारी इस टैक्स स्लैब में कमी की उम्मीद लगा रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि अरुण जेटली आम बजट 2018 में इससे जुड़ी घोषणा करेंगे। कारोबारी इस बजट से भी कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती की उम्मीद लगा रहे हैं।

2017-18 के बजट में लघु और सीमांत उद्योंगों के लिए टैक्स की दर को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर दिया गया था। यह कारोबारियों के लिए एक राहत भरा फैसला था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 50 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को ही 25 फीसद का टैक्स देना होता था। हालांकि, अब 25 फीसद के कॉरपोरेट टैक्स का दायरा 25 से 250 करोड़ के बीच की रेंज में आ गया है। इस घोषणा का फायदा बीते वित्त वर्ष (2016-17) में 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को भी मिला। मोदी सरकार की 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं के लिहाज से इसे अहम घोषणा माना गया ।उद्योग संगठन फिक्की ने सरकार को कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उसने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए कई अन्य सुझाव भी दिए थे, ताकि देश दूसरे देश की कंपनियों से मुकाबले करने की बेहतर स्थिति में आ पाए। फिक्की ने दलील दी थी कि जब दूसरे देशों में कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम किया जा रहा है तो भारत में भी इसमें कमी की जानी चाहिए ।बीते वित्त वर्ष कॉरपोरेट टैक्स की दरों में 5 फीसद की कटौती के बाद इस साल भी कारोबारियों और प्रतिनिधि संगठनों ने सरकार से बजट में राहत की अपील की है।

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को राहत! नए नियमों की मियाद 1 फरवरी से आगे बढ़ेगी : सूत्र

नई दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई से जुड़े नए नियम लागू होने की तिथि बढ़ सकती है. अभी ये नियम 1 फरवरी से लागू होना तय है. सरकार की तरफ से डेडलाइन को 2 से 3 महीने तक आगे बढ़ा सकती है. ऐसा होने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने वालों को अभी कुछ और दिन तक डिस्काउंट मिलना जारी रहेगा. आपको बता दें दिसंबर में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कर ई-कॉमर्स कंपनियों में एफडीआई से जुड़े नियमों को सख्त किया था. इस नियम के लागू होने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ऑनलाइन कंपनियां अपने प्लेटफार्म पर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी.

किसी माल के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म नहीं होगा

सरकार की सफाई के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियां मार्केट प्लेस कंपनियां है और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में ही 100 प्रतिशत एफडीआई की ऑटोमेटिक रूट के जरिये अनुमति है. सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार विक्रेताओं पर ई-कॉमर्स कंपनियां दबाव नहीं डाल सकतीं और विक्रेता अपना माल कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच सकेगा. कई मौकों पर नए फोन या प्रोडक्ट सिर्फ चुनिंदा ई-कॉमर्स साइट पर ही लॉन्च होते है लेकिन नए नियमों के बाद किसी माल के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म नहीं होगा.

ई -कॉमर्स कंपनियों की दलील

ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार को दलील दी है कि नए नियमों को समझने के लिए उन्हें पर्याप्त वक्त नहीं मिला है. ऐसे में छह महीने का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए. जानकारों का यह भी कहना है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन की प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की हजारों करोड़ की इन्वेंटरी कंपनी के पास पड़ी है इसलिए अगर नए नियम लागू होते हैं तो उस इन्वेंटरी के सामान को कंपनी अपने प्लेटफार्म पर नहीं भेज पाएगी.

सरकार पर अमेरिका से भी दबाव

दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 16 मिलीयन डॉलर का निवेश किया है और 77 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है. इसके बाद भारत में मौजूद दोनों बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर अमेजन और फ्लिपकार्ट का अमेरिका कनेक्शन है. अमेरिकी सरकार भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के हितों को देखते हुए भारत सरकार पर नियमों में ढील देने का दबाव बना रही है. अमेरिका की सरकार ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध अच्छे हैं इसलिए अमेरिकी कंपनियों के हितों की रक्षा रक्षा होनी चाहिए.

घरेलू मोर्चे पर विरोध

दूसरी तरफ घरेलू रिटेल संगठन 1 फरवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का लगातार विरोध कर रहे हैं. सीए आईटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई मांगे रखी है. पीएम को लिखे गए पत्र में साफ-साफ लिखा है कि 1 फरवरी की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाए. ई-कॉमर्स पॉलिसी को जल्द से जल्द जारी किया जाए. साथ ही जो कंपनियां ई-कॉमर्स पॉलिसी से जुड़े नियमों को मानती उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. आपको बता दें छोटे रिटेलर की हमेशा से शिकायत रही है कि नियमों का पालन नहीं करके ई-कॉमर्स कंपनियां गलत तरीके से डिस्काउंट दे रही है. चुनाव से ठीक पहले सरकार लाखों-करोड़ों छोटे रिटेलर्स को भी नाराज नहीं कर सकती.

ई-कॉमर्स कंपनियों पर होगया यह असर

फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अपनी सब्सिडियरीज बना कर उनके प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में अगर ई-कॉमर्स कंपनी की हिस्सेदारी है तो वो कंपनियां अपना या सब्सिडियरीज का माल नहीं बेच सकेंगी. ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विक्रेता भी जिम्मेदार होगा और दाम घटाने के लिए विक्रेता पर दबाव नहीं डाला जा सकता. यानी फ्लिपकार्ट और अमेजन भारी भरकम डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी. ऑफर्स पर भी ई-कॉमर्स कंपनियों को सफाई देनी होगी और कैश बैक देने में पारदर्शिता बरतनी होगी. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होने हैं.

चिटफंड मामला: ED ने राजस्थान की कंपनी की 2.09 करोड़ रू की संपत्ति की कुर्क

ईडी ने बताया कि उसने पुरस्कार चिट और धन संचरण प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा कंपनी और निदेशकों के खिलाफ दर्ज 48 प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद मामले को अपने हाथ में लिया।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने चिटफंड धनशोधन मामले में राजस्थान की एक कंपनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 2.09 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि मार्केटिंग कंपनी ओरो ट्रेड नेटवर्क इंडिया लिमिटेड की सम्पत्तियों को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। कुर्क संपत्ति का कुल मूल्य 2.09 करोड़ रुपए है ईडी ने बताया कि उसने पुरस्कार चिट और धन संचरण प्रतिबंध

अधिनियम 1978 के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा कंपनी और निदेशकों के खिलाफ दर्ज 48 प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद मामले को अपने हाथ में लिया। निदेशालय ने बताया कि उसकी जांच में पता चला कि ''कंपनी और उसके निदेशकों ने षड्यंत्र रचा और कई लोगों को अच्छे रिटर्न का वादा करके अपनी योजना में निवेश करने के लिए फुसलाया और आपराधिक षड्यंत्र से करीब 44 करोड़ रुपए एकत्र किए।''उसने बताया कि कंपनी और उसके निदेशकों सत्येंद्र शर्मा और संध्या शर्मा ने ''इस अपराध से हुए लाभ'' के माध्यम से कई चल और अचल सम्पत्तियां एकत्र कीं। ईडी ने इस मामले में अब तक 7.55 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क की है। उसने बताया कि ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है और मुख्य आरोपी सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत नामंजूर कर दी है।

शुरुआत में आधार में कई दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन अब कोई समस्या नहीं: नंदन नीलेकणि

दावोस: इन्फोसिस के अध्यक्ष और आधार कार्ड की परिकल्पना करने वाले नंदन नीलेकणि ने गुरुवार को कहा कि अनूठे राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना की शुरुआत में काफी सारी दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब सब कुछ सुलझ चुका है. उन्होंने कहा कि आधार कोई आंकड़े जुटाने का साधन नहीं है. बल्कि यह न्यूनतम आंकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग कर दो प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें एक है बुनियादी और विशिष्ट पहचान-पत्र प्रदान करना और दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे.

योजना बनाकर ृष्ठ्रक्र को बदनाम करने की कोशिश, राई को बनाया जा रहा पहाड़: नंदन नीलेकणि

यहां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 में %डिजिटल दुनिया में पहचान विषय पर आयोजित एक सत्र में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने कहा, %%भारतीय पहचान-पत्र प्रणाली को आधार कहा जाता है, जिसका अर्थ है नींव/बुनियाद और यह विचार 2006 में आया. इसके कई कारण थे, जिनमें नौकरी के लिए शहरों में जाने वाले लोग, बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड नहीं होना और और जिनके पास बुनियादी दस्तावेज नहीं हैं ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाना."

आधार से मोदी सरकार को 9 अरब डॉलर की बचत, डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा देश-नीलकेणि

नीलेकणि ने कहा कि लेकिन जैसे ही सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि बहुत सारा पैसा रास्ते में ही बर्बाद हो जा रहा है और फिर यह सोचा कि डिजिटल आईडी से लाभकारी योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

मिडिल क्लास को मिलेगी टैक्स में राहत या मायूस करेगा नया बजट?

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। 1 फरवरी 2019 को वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश किया जाना है। हालांकि, यह पूर्ण बजट न होकर वोट ऑन अकाउंट होगा यानी चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को सुचारू रुप से चालू रखने हेतु कुछ महीनों के लिए पेश किया जाने वाला अंतरिम बजट होगा ।वर्ष 2018-19 के बजट में आम आदमी के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई थी, लेकिन मध्य वर्ग को और ज्यादा राहत की उम्मीद थी। बीते वर्ष का आम बजट देश के मिडिल क्लास के लिए मायूसी लेकर आया। इस बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं

मिली। जहां एक ओर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे बाहर से आने वाले उत्पादों का महंगा होना सुनिश्चित हो गया। वहीं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस को 3 फीसद से बढ़ाकर 4 फीसद कर दिया गया ।अंतरिम बजट पर टिकी नजरें- 1 फरवरी को पेश होने वाले वोट ऑन अकाउंट से लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन को लेकर है। पिछली बार लोगों ने राहत की उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा था। लोग यह भी चाहते हैं कि बैंक अपनी दरों को कम करे, ताकि उन्हें सस्ता लोन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा महंगाई के मोर्चे पर और राहत भी देश के आम आदमी की उम्मीदों में शामिल है ।रोजगार को लेकर मध्य वर्ग ने इस सरकार से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। सरकार ने पिछले पांच सालों के दौरान वादे के मुताबिक रोजगार के अवसर पैदा करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इस दिशा में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस बजट के दौरान लोगों की नजरें सरकार की उन घोषणाओं पर भी होगी, f

अंतरिम बजट 2019: बजट भाषण में इस्तेमाल होने वाले 6 शब्दों का ये है अर्थ

नई दिल्ली: अंतरिम बजट पेश होने से 9 दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं. इससे साफ हो गया है कि इस बार इस बार अंतरिम बजट अरुण जेटली नहीं बल्कि पीयूष गोयल पेश करेंगे. मोदी सरकार की तरफ से 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. ऐसे में हम आपको बजट की कुछ शब्दावलियों के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल बजट भाषण में खूब होता है. इन शब्दावलियों का इस्तेमाल कई संदर्भों में किया जाता है. इससे आप बजट भाषण को आसानी से समझ सकेंगे.

फाइनेंसियल बिल (वित्तीय विधेयक)

बजट एक वित्तीय विधेयक होता है. इसमें नई सरकार की नीतियां, नए कर प्रस्ताव और वर्तमान कर ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव शामिल होते हैं. वित्त मंत्री सदन में बजट भाषण पढ़ते हैं और इसे संसद की मंजूरी के लिए सदन में पेश करते हैं. इसमें सबसे अहम बात यह है कि संविधान में वित्तीय विधेयक के लिए कुछ विशेष नियम हैं. इस नियम के मुताबकि वित्तीय विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने में राज्यसभा अड़ंगा नहीं लगा सकती. अगर सरकार के पास ऊपरी

सदन में विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी. जबकि अन्य विधेयकों को संसद की मंजूरी के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूर है.

कैबिटल रिसिप्ट/एक्सपेंडिचर (पूंजीगत आय/व्यय)

किसी भी बजट में कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें होती हैं. परिसंपत्ति निर्माण या मशीनरी या जमीन के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल धन को पूंजीगत व्यय कहा जाता है. इसके अलावा सरकार को जो धन उधार या परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होता उसे पूंजीगत आय कहते हैं.

पब्लिक अकाउंट

भविष्य निधि और छोटी बजत पब्लिक अकाउंट के तहत आती है. लोग भविष्य के लिए इन खातों में धन जमा करते हैं. यहां यह समझने की जरूरत है कि सरकार इन खातों में मौजूद धन का मालिक नहीं होती लेकिन वह इनका अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है. कुल मिलाकर वह इन खातों के मामले में एक बैंकर की तरह काम करती है.

फिसकल डेफिसट (वित्तीय घाटा)

एक वित्त वर्ष में सरकार जब अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो तब वित्तीय घाटे की स्थिति पैदा होती है. सरकार हमेशा से वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश करती है. इसके लिए वह अपने खर्च पर नियंत्रित करती है. वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है. पिछले कुछ सालों से भारत सरकार का वित्तीय घाटा 2.5 फीसदी से 3.5 फीसदी के बीच रहता आ रहा है.

ट्रेजरी बिल

ट्रेजरी बिल या टी-बिल सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं जो एक साल के भीतर ही परिपक्व (मैच्योर) होती हैं. सरकार उस वक्त टी-बिल जारी करती है जब खास वित्त वर्ष में खर्च को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व यानी धन नहीं होता.

कंटीजेंसी फंड (आपातकालीन कोष)

सरकार के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन कोष होता है.

पल्सर के बाद आ रही Bajaj की एक और दमदार बाइक, अगले महीने होगी लॉन्च

नई दिल्ली : नया साल शुरू होते ही ऑटो कंपनियां नए-नए व्हीकल लॉन्च कर रही हैं. इसका असर वाहन बाजार में भी दिखाई दे रहा है और ऑटो मार्केट रफ्तार पकड़ने लगा है. नई वैगनआर, टाटा की एसयूवी हैरियर और निसान की किक्स लॉन्च होने के बाद नए टू-व्हीलर की रेंज सड़क पर आने के लिए तैयार है. अब बजाज ने अपनी सुपर बाइक डोमिनर 400 (Bajaj Dominar 400) की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली है. फरवरी में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा. यह बजाज की पल्सर के बाद एक और दमदार बाइक होगी. कंपनी की तरफ से डॉमिनर की बुकिंग शुरू हो चुकी है.

कंपनी डोमिनर के साथ नई एवेंजर को भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. दोनों ही बाइक्स BS-4 तकनीक के साथ पेश की जाएंगी और इनमे´ ABS (एंटी ब्रेकिंग सिस्टम) फीचर्स भी होगा. डोमिनर बजाज की सबसे पावरफुल महंगी बाइक्स में से होगी. इसकी कीमत डेढ़ लाख से लेकर 1.65 लाख रुपये के बीच रखी गई है. नॉन एंटी ब्रेकिंग सिंस्टम वाली बाइक की कीमत 1.49 लाख रुपये और एबीएस सिस्टम वाली बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.63 लाख रुपये तय की गई है. हालांकि इसकी बुकिंग पर कुछ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.

पावरफुल इंजन

डोमिनर 400 में 373 सीसी लिक्विड-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. सिंगल-सिलिंडर इंजन 35 ङ्खद्धश्च पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. डोमिनर में 6-स्पीड गियरबाक्स दिया गया है, जो स्लिपर क्लच और स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ है. डोमिनर 148 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से दौड़ सकती है. मोटरसाइकिल में ट्विन पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलेगा जो पहले की तुलना में एक थ्रोट साउंड पैदा करेगा.

मौजूदा बाइक से 10 हजार रुपये ज्यादा होगी कीमत

नई डोमिनर 400 में शानदार ग्राफिक्स, आकर्षक रंग, फंकी और स्पोर्टी लुक दिया गया है. इसके इंजन में डबल ओवरहेड कैम लेआउट दिया गया है. बाइक में 320 एमएम का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 230 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है. ज्यादा सेफ्टी के लिहाज से एंटी ड्युल ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. उम्मीद की जा रही है कि नई डोमिनर की कीमत मौजूदा बाइक से 10 हजार रुपये तक ज्यादा होगी.

सूरत। सूरत महानगर पालिका के दबान विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक दिव्यांग लड़के की व्हीलचेयर सिविल चार रास्ते के पास जप्त कर ली। जिसके कारण दिव्यांग लड़के को इधर उधर ले जाना उनके परिवार के लिए कठिन हो गया। सूरत महानगर पालिका के दबान खाते वाले पहले लारी गल्ला को ही उठाते थे लेकिन अब तो वे शारीरक रुप से अपंग लोगों की व्हीलचेयर तक को जप्त कर ले रहे है।

सूरत। शहर के जोलवा में आने वाले बगमुरा इलाके में बुधवार रात में लगी आग इतनी भयंकर थी किफायर ब्रिगेड़ ने ब्रिगेड कोल जाहिर कर दिया था। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। जिसमें से तीन लोगों की डेड बोडी बरामद कर ली गई है, लेकिन एक व्यक्ति की डेड बोडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसकी जांच अभी भी चल रही है। सूत्रों से मिली ाजनकारी के अनुसार जिन चार लोगों की मौत हुई है वे सभी परप्राति थे। ये लोग प्लास्टिक फेक्ट्री में ही काम करते थे और वहीं पर रहते थे। जिस कारण जब फैक्ट्री में आग लगी वे सभी आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।

सूरत। शहर के बमरोली इलाके में शुक्रवार की सुबह एक गाय मकान बनाने लिए बनाई गई फाउंडेशन के गढे में गिर गई, जिसे निकालने के लिए समाज के जागरुक लोगों द्वारा पहले क्रेन बुलाई गई जिसकी मदद से गाय को बाहर निकाला गया। इस घटना में गाय को काफी चोट भी आई लेकिन गरिमत यह रही की गाय की जान बच गई। उधना जोन के अधिकारियों द्वारा गैर कायदेसर बनाय जा रहे घरों पर पुरी निगरानी नहीं कि जा रही है इसी का परिणाम है कि उधन जोन में गैर कायदेसर बांधकाम की बाढ आई हुई है, और इन सब बांधकामों से जनता तो जनता अब जानवार भी परेशान होने लगे और कई की तो जान पर भी बन आई है।

सूरत रेल्वे स्टेशन पर 100 फुट उंचे तिरंगे को लहराया

सांसद दर्शना बने जरदोश ने फहराया तिरंगा

सूरत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सूरत रेल्वे स्टेशन परिशर में शुक्रवार को 100 फुट उंचा राष्ट्रध्वज लेहराया गया। जो आज से हमेशा के लिए लहराता रहेगा। देश के ए-1 ग्रेड रेल्वे स्टेशन में सूरत रेल्वे स्टेशन परिशर में शुक्रवार को सांसद दर्शना बेन जरदोश के हाथों 100 फुट उंचा राष्ट्रध्वज लहराया गया है। रेल्वे बोर्ड द्वारा डिसेंबर 2018 में राष्ट्रध्वज लेहराने के लिए बताय गया था। जोके डेडलाईन चुक गया बाद में प्रजासत्तक पर्व के पहले 25 जनवरी को राष्ट्रध्वज को लहराने के निर्णय लिया गया। सूरत रेल्वे स्टेशन के उपरांत देश के 75 ए-1 ग्रेड के स्टेशनों पर राष्ट्रध्वज को लहराया गया है। पश्चिम रेल्वे मुबई मंडल के बांद्रा टर्मिनल, मुबंई सेन्ट्रल और सूरत रेल्वे स्टेशन पर राष्ट्रध्वज को लगाने का आदेश दिया गया था। राष्ट्रध्वज सम्मान नियमों के नियमों को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी उंचाई पर लहराते राष्ट्रध्वज की सुरक्षा काफी चुस्त रेहगी। सूरत रेल्वे स्टेशन परिसर में राष्ट्रध्वज की सुरक्षा की जवाबदारी आरपीएफ को सोंपी गई है।

आज के कार्यक्रम में बड़ी स ंख्या में लोग उपस्थित रहे और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस मुद्दे पर सूरत रेल्वे स्टेशन पर मुसाफीरों ने बताया कि ऐक भारतीय अपने लिए गर्व की बात है परंतु रेल्वे द्वारा सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। बहुंत सारे मुसाफिरों द्वारा राष्ट्रध्वज को लहराने के निर्णय को समर्थन दिया गया कि तिरंगा देश की शान है। सूरत रेल्वे स्टेशन पर 100 फुट उंचा तिरंगा लहराना गर्व की बात है।

सभी वर्गों को साथ लेकर करना है राज्य का सर्वांगीण विकास: मुख्यंमत्री

लिव फॉर द नेशन के मंत्र के साथ देश के विकास में जुड़े युवा शक्ति

बनासकांठा। मुख्यंमत्री विजय रूपाणी ने कहा कि प्रजा के सभी वर्गों का समावेश कर लोगों की आशा-अपेक्षाओं को पूरा कर राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलने वाला शासन ही लोगों की आशा-अपेक्षाओं को परिपूर्ण कर सकेगा। 70वें गणतंत्र दिवस के राज्यस्तरीय समारोह के तहत शुक्रवार को पालनपुर में आयोजित युवा स मेलन में उन्होंने यह बात कही।

विजय रूपाणी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के आधार पर भारत के नागरिकों को बोलने, व्यापार चलाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी इच्छित सरकार का गठन कर सकती है। उन्होंने कहा कि अनेक प्रसिद्ध व गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के कारण भारत को आजादी मिली है। अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, आज का दिन उन सभी बलिदानियों को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब देश में गरीबी, बेरोजगारी और शोषण था। आजादी के इतने वर्षों बाद अब हमने स्वराज से सुराज की दिशा में कदम बढ़ाया है। युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व 'डाई फॉर द नेशन' युवाओं का मंत्र था। अब वर्तमान परिस्थितियों में 'लिव फॉर द नेशन' का मंत्र युवाओं को आत्मसात करना चाहिए।

मुख्यंमत्री ने कहा कि समाज में जाति, धर्म और पंथ के भेदभाव के बिना एक और नेक बनकर सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ही राज्य एवं देश आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने अटल जी की कविता का पाठ करते हुए युवाओं से प्रखर राष्ट्रवाद अपनाकर देश की प्रगति में सहभागी बनने की अपील की। वाइब्रेंट समिट की सफलता का जिक्र करते हुए रूपाणी ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूरा होने तक यानी 31 मार्च, 2019 तक राज्य में 450 कंपनियों द्वारा 1.11 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न निवेशों का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ होने जा रहा है। इसके चलते लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह वाइब्रेंट समिट की सफलता है। हर हाथ को काम, किसानों को योग्य दाम देने के साथ ही गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों तक विकास का फल पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 60 फीसदी आबादी युवा हो, तब मां भारती को परम वैभव के शिखर तक ले जाने की जवाबदारी विशेष रूप से युवाओं की बनती है। मुख्यंमत्री ने आयुष्मान भारत, उज्जवला योजना, मा अमृतम और मा वात्सल्य योजना के जरिए लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में पैदा हुए रोजगार में से 74 फीसदी नौकरियों का सृजन अकेले गुजरात में हुआ है। इस वर्ष 75 हजार युवाओं को अप्रेंटिस योजना के तहत रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इसी तरह, गुजरात राज्य लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना है।रूपाणी ने कहा कि गुजरात ने स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। राज्य 11 फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर से विकास कर रहा है और अनेक नीतियों के सफल क्रियान्वयन द्वारा गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है।

मुख्यंमत्री कहा कि पहले राज्य में सिर्फ 8 विश्वविद्यालय कार्यरत थे जबकि आज 62 विश्वविद्यालय कार्यरत कर यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र की शिक्षा से वंचित न रहे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**